महत्वपूर्ण एवं खास

किडनी रोड पीड़ित ग्रामीण तक मुख्यमंत्री ने भिजवाई मदद

» वदेश में रहकर भी जनता का पूरा ध्यान रख रहे हैं सीएम

रायपुर (आरएनएस)। किडनी की बीमारी से बुरी तरह से पीड़ित सुपेबेड़ा के ग्रामीण की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री ने तत्काल पीड़ित मरीज तक मदद पहुंचाने का निर्देश दिया, इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता ने बकायदा अस्पताल पहुंचकर पीड़ित के बिल का भुगतान किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों यूएसए (अमेरिका) के प्रवास पर हैं। पर विदेश जाने के बाद भी वे छत्तीसगढ़ के हर गतिविधियों की जानकारी लेते आ रहे हैं। इसी क्रम में उन्हें जब यह पता चला कि सुपेबेड़ा के एक गरीब ग्रामीण का उपचार राजधानी के एक निजी अस्पताल में चल रहा है तथा उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री ने सहृदयता का परिचय देते हुए तत्काल पीड़ित मरीज तक मदद पहुंचाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री का निर्देश मिलते ही कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी अस्पताल पहुंचे और मरीज के 3 लाख 32 हजार रूपए के बिल का भुगतान किया। बताया गया कि सुपेबेड़ा निवासी दुर्योधन पुरैना गंभीर रूप से किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं और उनका इलाज राजधानी के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। इलाज के लिए दुर्योधन को अस्पताल में 3 लाख 32 हजार भुगतान करना था। इस बात की जानकारी सीएम भूपेश बघेल को लगी तो उन्होंने तत्काल उसकी मदद की।

संस्कृति विभाग 19 को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर तात्यापारा में कार्यक्रम आयोजित करेगा

रायपुर (आरएनएस)। नगर निगम रायपुर के संस्कृति विभाग के प्रभारी अधिकारी हेमंत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम संस्कृति विभाग ने राजधानी के मेजर यशवंत गोरे चौक तात्यापारा में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की अष्वारोही प्रतिमा के सामने उनकी जयंती पर उन्हें ससम्मान नमन करने दिनांक 19 फरवरी 2020 को सुबह 10 बजे जयंती कार्यक्रम रखा है।

हाईकोर्ट ने राज्य में 58 प्रतिशत आरक्षण पर रोक यथावत रखा

» चार सप्ताह बाद पुनः होगी सुनवाई

रायपुर (आरएनएस)। राज्य में 58 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के मामले में राज्य सरकार की दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में 4 हफ्ते बाद पुनः सुनवाई की तारीख तय की है। राज्य में 58 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के मामले में राज्य सरकार की दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उच्चन्यायालय ने 58 प्रतिशत आरक्षण पर लगी रोक को यथावत रखते हुए इस प्रकरण में चार सप्ताह बाद पुनः सुनवाई करने की बात कही है। राज्य सरकार की ओर से याचिका में आरक्षण को 50 प्रतिशत तक करने की अपील की गई है। ज्ञात हो कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद ही कांग्रेस सरकार ने राज्य के अंदर निवासरत अन्य पिछड़ा वर्ग के अ भ्यर्थियों का आरक्षण बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था।

नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया 20 को मिलेंगे राजीव भवन में कांग्रेसजनों से

रायपुर (आरएनएस)। 20 फरवरी गुरूवार को मिलिये मंत्री से कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन, विकास एवं श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया दोपहर 1 बजे से राजीव भवन में बैठेगे। इस दौरान मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियो और जनसामान्य से मुलाकात कर अपने विभाग से संबंधित समस्याओं शिकायत एवं सुझाव पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि डॉ. शिवकुमार डहरिया मुलाकात कार्यक्रम के बाद राजीव भवन में उपस्थित मीडिया के साथियों से भी चर्चा करेंगे।

मिलिये मंत्री कार्यक्रम में 19 को राजीव भवन में उपस्थित रहेंगे मंत्री जयसिंह अग्रवाल

रायपुर (आरएनएस)। मिलिए मंत्री कार्यक्रम के तहत परसों 19 फरवरी बुधवार को राज्य के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग मंत्री जयसिंह अग्रवाल दोपहर 12 बजे से राजीव भवन में बैठेगे। इस दौरान मंत्री जयसिंह अग्रवाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं,पदाधिकारियो और जनसामान्य से मुलाकात कर अपने विभाग से संबंधित समस्याओं शिकायत एवं सुझाव पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

नजूल भूमि पट्टों को फ्री-होल्ड करने के लिए शिविर लगाये - राजस्व सचिव

रायपुर। नजूल भूमि पट्टों को फ्री-होल्ड करने के लिए शिविर लगाये - राजस्व सचिवराजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव सुश्री रीता शांडिल्य ने राजस्व अधिकारियों से कहा है कि नगरीय क्षेत्रों में रियायती और गैर रियायती स्थाई पट्टों पर प्राप्त नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने के लिए नगरीय क्षेत्रों के विभिन्न वार्डो में शिविर लगाये जाएं। इसकी जानकारी हितग्राहियों को देने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें, जिससे उन्हें शासन की इस आकर्षक योजना से उन्हें लाभान्वित किया जा सके। राजस्व सचिव ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार सहित कबीरधाम जिले की नजूल अधिकारियों

की बैठक लेकर इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिये। राजस्व सचिव ने बैठक में अधिकारियों से जिलेवार नगरीय क्षेत्रों में नजूल भूमि के बंटन के प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होंने नगरीय क्षेत्र में गैर रियायती दर और रियायती दर में आबंटित भूमि के हितग्राहियों को उनकी भूमि फ्री-होल्ड करने के लिए किये जा रहे कार्यो की जानकारी लेते हुए कहा कि फ्री-होल्ड के फायदा से उन्हें अवगत कराया जाए। इसके लिए अधिकारियों को व्यापक-प्रचार करने के निर्देश दिए गए। इसी तरह से राजस्व सचिव ने नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन करने के लिए शासन निर्देशानुसार समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने अतिक्रमित भूमि को चिन्हांकित कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिये। राजस्व सचिव ने गृह निर्माण सहकारी समितियों तथा सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को रियायती दर पर आबंटित भूमि को फ्री होल्ड किये जाने के संबंध में शासन के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में जानकारी तैयार कर संबंधित संस्थाओं की सूची शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। बैठक में अधिकारियों से राजस्व वसूली के कार्य में प्रगति लाने के लिए तत्परता से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। अधिकारियों से सिंधी विस्थापित परिवारों के विस्थापन के संबंध में भी जानकारी ली गई।

बैठक में नजूल भूमि के डायवर्सन, व्यवस्थापन, शासकीय भूखण्डों के नियमितीकरण, विभिन्न राजस्व प्राप्तियों की प्रविष्टि, भूमि स्वामी हक सहित नजूल अधिकारियों को ई-कोर्ट के तहत कार्यवाही करने के कार्यो की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से उनके कार्यो में आने वाली समस्याओं की भी जानकारी ली। इस अवसर पर आयुक्त भू-अभिलेख श्री रमेश शर्मा सहित राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

कुपोषण मुक्ति अभियान में मैदानी अमले सक्रियता से कार्य करें अनिला भेंड़िया

» वजन त्यौहार अभियान को मिशन मोड में संचालित करने के निर्देश

» महिला बाल विकास की समीक्षा बैठक संपन्न

रायपुर। महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया ने कहा है राज्य में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा तय किए गए लक्ष्य अनुरूप आगामी तीन वर्ष में राज्य में कुपोषण दूर किया जाना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैदानी स्तर के सभी अधिकारी और कर्मचारी सक्रियता से जुट जाए। उन्होंने कहा कि सुपोषण अभियान में लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वे आज राजधानी के न्यू सर्किट हाउस में मैदानी स्तर पर कार्य करने वाले विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थीं।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती भेंड़िया ने कहा कि सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन कर लिया जाए, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को पोषण पुर्नवास केन्द्रों में भर्ती कराया जाए। उन्होंने कहा कि कुपोषित बच्चों के पहचान के लिए नियमित रूप से वजन लेना जरूरी है।

पोषण पखवाड़े के दौरान सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में 8 से 22 मार्च तक केन्द्र में दर्ज बच्चों का वजन अनिवार्य रूप से लिया जाए। कोई भी बच्चा वजन लेने से न छूटे। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि हर गर्भवती शिशुवती माताओं को रेडी-टू-इट आहार का वितरण किया जाए। इसी प्रकार बच्चों को गर्म भोजन और नास्ता बदल-बदलकर दिया।

मुख्यमंत्री की नोबल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी से मुलाकात

» मुख्यमंत्री के अनुरोध को स्वीकारा- जुलाई माह में छत्तीसगढ़

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के अमेरिका प्रवास के दौरान बोस्टन में एमआईटी केम्ब्रिज में नोबल पुरस्कार विजेता श्री अभिजीत बनर्जी से सौजन्य मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अर्थशास्त्री श्री अभिजीत बनर्जी को नोबल पुरस्कार मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी।

इस वर्ष अर्थशास्त्र के नोबल पुरस्कार विजेता प्रो. अभिजित बनर्जी के साथ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने टीम के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के आर्थिक विकास के विभिन्न प्रयोगो पर विस्तार से चर्चा की । चर्चा के दौरान श्री बघेल ने

छत्तीसगढ़ के अभिनव प्रयोग नरवा, गरुवा, घुरुवा और बाड़ी, हॉट बाजार क्लिनिक योजना, सुपोषण अभियान और एथेनाल प्रोजेक्ट विषयों पर विस्तार से बातचीत की। प्रो. बनर्जी ने छत्तीसगढ़ सरकार के इन प्रत्येक प्रयोगों को सराहा। प्रो. बनर्जी ने नवाचारों के इन सफल प्रयोगों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आर्थिक विकेन्द्रीकरण के लिए विशेष चिन्हित इलाकों को क्लस्टर अप्रोच से डिजाइन करने व मॉनिटरिन्ग पर जोर दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ आकर प्रयोगो को देखने की मुख्यमंत्री के अनुरोध को स्वीकार करते हुए जुलाई के आस पास राज्य में आने की सहमति भी दी। प्रो बनर्जी के सहयोगियो के साथ मुख्य सचिव श्री मंडल, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री गौरव द्विवेदी, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा एवं हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रही प्रदेश की सचिव सुश्री एम् गीता भी उपस्थित थी। लगभग डेढ घंटे के इस संवाद के बाद प्रो. बनर्जी ने अपने हस्ताक्षर के साथ अपनी किताबें भी मुख्यमंत्री को भेट कीं।

दुर्ग जिले में बेलौदी जलाशय के जीर्णोद्धार कार्यो के लिए लगभग छह करोड़ रूपए राशि स्वीकृत

रायपुर। राज्य शासन ने दुर्ग जिले के विकासखण्ड पाटन की बेलौदी जलाशय तथा नहरों का जीर्णोद्धार एवं लाइनिंग कार्यो को कराने छह करोड़ 6 हजार रूपए स्वीकृत किए है। जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से इस कार्य को कराने के लिए मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार जल संसाधन विभाग रायपुर को प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। जलाशय योजना के निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर क्षेत्र में कुल 368 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार हो जायेगा।

विशेष लेख वनांचलों का विकास : नए फैसले नई रणनीति

» लेख-जी.एस. केशरवानी

रायपुर। प्रदेश में लगभग एक तिहाई आबादी अनुसूचित जनजातियों की है। आदिवासी अंचलों के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा तेजी से नए फैसले लिए जा रहे है। इन फैसलों को तेजी से क्रियान्वित किया जा रहा है। वनांचल में रहने वाले आदिवासी समुदाय के जनजीवन को आसान बनाने के लिए नए रास्ते तलाशने शुरू कर दिए हैं। स्थानीय लोगो को मूलभूत सुविधाएं देने का मुद्दा हो या रोजगार का मुद्दा हो इन सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। आदिवासी समुदाय की संस्कृति संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव अब राज्योत्सव के समय आयोजित होगा। राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति 'गढ़बो नवा छत्तीसगढ़' की मूल भावना पर आधारित है। इस नीति के माध्यम से आदिवासी अंचलों के विकास में तेजी आएगी और रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। उद्योग नीति में पिछड़े क्षेत्रों या विकासखंडों को सबसे अधिक रियायत और संसाधन देने का फैसला किया गया है। कोण्डागांव जिले के ग्राम कोकड़ी में 5 करोड़ रूपए की लागत से सहकारी क्षेत्र में मक्का प्रोसेसिंग यूनिट, जिला मुख्यालय सुकमा और बस्तर जिले के धुरागांव में फूड पार्क का शिलान्यास किया गया है।

नई सरकार ने बस्तर के लोहांडीगुड़ा और तोकापाल में उद्योग के लिए अधिग्रहित की गई भूमि आदिवासी किसानों को वापस करने का निर्णय लिया। राज्य में उत्पादित होने वाले हर्बल वनौषधि तथा लघु वनोपज आधारित उद्योगों को उच्च प्राथमिकता के अंतर्गत अधिकतम व्याज अनुदान, नेट जीएसटी प्रतिपूर्ति, स्टाम्प ड्यूटी छूट विद्युत शुल्क छूट देने का प्रावधान किया गया है।

जबर्रा में पर्यटन विकास की गूंज राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची

धमतरी। मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में आयोजित ''सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन एवं आजीविका के अवसर'' विषय आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला-सह-सेमिनार में कलेक्टर श्री रजत बंसल ने जिले के जबर्रा में पर्यटन विकास की संभावनाओं तथा जिला प्रशासन द्वारा मुहैय्या कराई जा रही सुविधाओं पर व्याख्यान दिया। इस तरह पर्यटन विकास की दृष्टि से जबर्रा को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली। प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आरपी मंडल ने उक्त कार्यशाला में हिस्सा लेने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एवं आयुक्त, आदिवासी विकास श्री मुकेश कुमार बंसल और जिले के कलेक्टर श्री रजत बंसल का चयन किया था। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) में रविवार 16 फरवरी के दोपहर में आयोजित सेमिनार के उद्घाटन सत्र में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे जिले के कलेक्टर ने आदिवासी बाहुल्य जबर्रा के वन क्षेत्र में पर्यटन के विकास हेतु विगत छह माह में किए गए कार्यों तथा गतिविधियों पर प्रकाश डाला। साथ ही भविष्य में आने वाली चुनौतियों व स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार की गई कार्ययोजनाओं का पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) के माध्यम से सिलसिलेवार प्रस्तुतिकरण किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अगस्त 2019 में जिले के प्रवास के दौरान जबर्रा को ईको टुरिज्म के तौर पर विकसित करने की घोषणा की थी।

बाहर से आने वाले बसों के लिये बनाये जायेंगे अस्थायी अड्डे

बिलासपुर। बिलासपुर शहर में यातायात के दबाव को कम करने के लिये बाहर से आने वाले बसों का रूट निर्धारित किया जायेगा और उनके लिये अस्थायी अड्डे बनायें जायेंगे। बिलासपुर शहर में सुव्यवस्थित यातायात के लिये आयोजित बैठक में कलेक्टर डॉ.संजय अलंग द्वारा आरटीओ को निर्देशित किया कि इस संबंध में बस ऑपरेटरों से बातचीत इस कार्ययोजना को मूर्तरूप दिया जाये। उल्लेखनीय है कि बिलासपुर शहर में यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिये कलेक्टर डॉ.अलंग एवं पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा इसके लिये हर हफ्ते संयुक्त रूप से बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। आज बैठक में कलेक्टर ने शहर के सभी प्रमुख मार्गों में मार्किंग और संकेतक लगाने का कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ करने का निर्देश दिया। नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि इसके लिये रि-टेण्डर जारी कर दिया गया है। आरटीओ श्री शर्मा ने शहर में ऑटो के लिये चिन्हांकित किये जा रहे स्थलों की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि महाराणा प्रताप चौक से महामाया चौक तक ऑटो स्टैण्ड के लिये जगह प्राथमिकता से चिन्हांकित किया जाए। पुलिस अधीक्षक ने महाराणा प्रताप चौक में सड़क मार्किंग कार्य नहीं होने पर नाराजगी जताई। नगर निगम के अधिकारी को निर्देशित किया गया कि सड़कों में जेब्रा कॉसिंग के लिये जल्द से जल्द सूची बनाएं। मिट्टी तेल गली का कार्य भी जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। सड़क निर्माण में आ रही ट्रांसफार्मर की बाधाओं पर भी जल्द से जल्द कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया। शहर में 12 स्थल चिन्हांकित किये गये हैं जहां सड़कों से ट्रांसफार्मर हटाये जाने हैं। शहर के नेहरू चौक, सिम्स, तिफरा ओव्हरब्रिज और सिविल लाईन थाना क्षेत्र में हमेशा यातायात का दबाव बहुत ज्यादा रहता है।

बच्चों को जीवन कौशल स्कूली शिक्षा के दौरान ही दिए जाने चाहिए

» शिक्षकों ने सीखी जीवन कौशल विकास की अवधारणा

रायपुर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से 10 जीवन कौशल बताए गये है। बच्चों को जीवन कौशल स्कूली शिक्षा के दौरान ही दी जानी चाहिए। यह जानकारी कार्यशाला में प्रशिक्षण देने आए हरियाणा की अपराजिता के मैनेजर भारत भूषण ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रायपुर में जीवन कौशल से संबंधित शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित करते हुए दी। प्रशिक्षण में प्रदेश के लगभग 100 टीचरों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का आयोजन अपराजिता फाउंडेशन की ओर से दो बैच में किया गया।

कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों से चर्चा में कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से बताए गए जीवन कौशल को आधार

बनाते हुए अपराजिता फाउंडेशन ने सैकडों से अधिक वीडियो कार्यक्रम बनाए है। इनमें अनेक जीवन कौशलों के विकास की प्रक्रिया और उनके प्रयोग करने की विधि सुझाई गई है। उन्होंने बताया कि अपराजिता फाउंडेशन के जीवन कौशल का यह कार्यक्रम हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उतराखंड, झारखंड, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान आदि में संचालित हुआ है। जिसके बहुत सकारात्मक परिणाम सामने आए है।

समग्र शिक्षा के सहायक संचालक डॉ. एम. सुधीश ने बताया कि जीवन कौशल में वह योग्यताएं निहित है जो हर व्यक्ति के भीतर विकसित होनी चाहिए। यह व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों का सामना करने और स्वस्थ, प्रसन्न, रचनात्मक तथा संतुष्ट जीवन के अवसरों की आशा जगाने के लिए समर्थ बनाती है। जीवन कौशलों को प्रभावी रूप से शैक्षिक प्रक्रमों के साथ एकीकृत कर ही इसको सही अर्थों में लागू कर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंर्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU